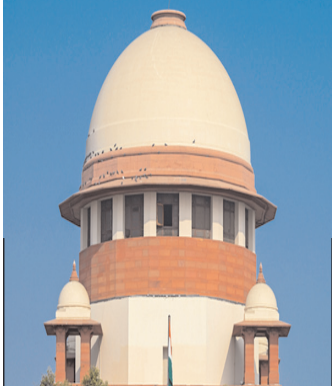
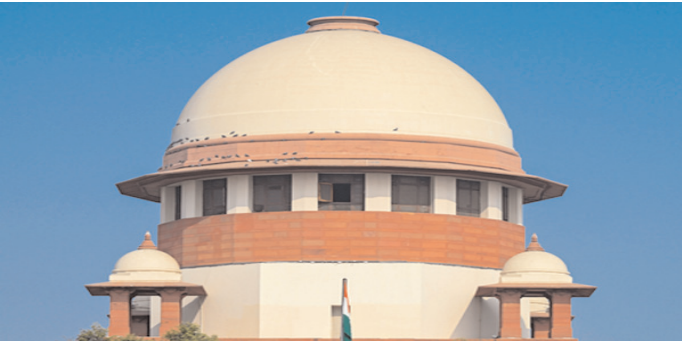




सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के दावों को बताया गलत

15 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली(एजेंसी)। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े मामलों में से एक, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के दावों को गलत बताया और अपनी दलील रखने के लिए कम से कम चार घंटे का समय मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच कर रही है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और तीर-कमान का निशान भी दिया था। इसी फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने दलीलें रखीं।



इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच कर रही है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और तीर-कमान का निशान भी दिया था। इसी फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने दलीलें रखीं।

धांधली या गड़बड़ी का समाधान उसे सुधारना चाहिए, न कि चुनावों को खत्म करना। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए पैसे देने को तैयार है, वह पद पाने के लिए पैसे नहीं देगा।’ दूसरा तर्क यह था कि सभी वरिष्ठ पदों के लिए चुनाव होते हैं। निचले स्तर के पदों पर मौजूद लोग केवल ऊपर से आए फैसले और नीतियां

लागू करते हैं, इसलिए उन्हें चुने जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, अगर चुनाव किसी के लिए भी आवश्यक हैं, तो वे उन लोगों के लिए हैं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में रहते हैं। वे जनता को नब्ब समझते हैं, मतदाताओं से सीधी बातचीत करते हैं और पार्टी को लोग केवल ऊपर से आए फैसले और नीतियां

बावल-बहरोड़ आरआरटीएस परियोजना की पूरक डीपीआर की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

राज्य की सैद्धांतिक स्वीकृति जल्द भेजने के निर्देश, 7,747 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनेगा खंड

जयपुर(एजेंसी)। नमो भारत रेल कॉरिडोर के तहत दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के बावल-बहरोड़ खंड को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर चर्चा की गई। साथ ही परियोजना के लिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पूरक डीपीआर को शीघ्र अनुमोदन के लिए भेजने के निर्देश



दिए। उन्होंने कहा कि सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव जल्द आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि आरआरटीएस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। बैठक में बताया गया कि सराय काले खां से बहरोड़ तक प्रस्तावित रेल कॉरिडोर की कुल

लंबाई 129.05 किलोमीटर है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 25.16 किलोमीटर होगा। राजस्थान क्षेत्र में शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़, शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड़ सहित चार एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। बावल-बहरोड़ खंड की अनुमानित लागत 7,747 करोड़ रुपये है। इसमें 5,167.28 करोड़ रुपये मूल परियोजना लागत, करीब 640 करोड़ रुपये भूमि लागत और 1,861 करोड़ रुपये उद्यम निधि के रूप में शामिल हैं। बैठक में परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, चरणबद्ध व्यय और राज्य सरकार के वित्तीय दायित्वों पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव

ने परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के संबंध में जिला कलक्टर, कोटपुतली-बहरोड़ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान-हरियाणा सीमा तक की लागत दोनों राज्यों द्वारा वहन किए जाने तथा हरियाणा सरकार से प्राप्त समझौता ज्ञापन के निष्पादन पर भी चर्चा हुई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त, वित्त (राजस्व) विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जर्जर स्कूल की मरम्मत शुरू, सीजेपी ने बताया छात्रों की जीत

जयपुर(एजेंसी)। राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर के जर्जर और क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का अभियान शुरू किया है। जयपुर के बगरू क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल में मरम्मत कार्य शुरू होने पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इसे छात्रों की जीत बताया। रांका ने कहा कि इस स्कूल में दो साल से अधिक समय से छात्र भैंसों के बाड़े में पढ़ने को मजबूर थे। 21 अगस्त को स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी की टीम पर कथित हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विरोध और हमले के बावजूद स्कूल में मरम्मत कार्य शुरू होना



राहत की बात है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सीजेपी कर रहे हुए उन्होंने कहा कि विरोध और हमले के बावजूद स्कूल में मरम्मत कार्य शुरू होना

बैरवा ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए अभियान शुरू किया है। जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान कर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। जरूरत वाले स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। बैरवा ने कहा कि कई स्कूलों की इमारतें काफी पुरानी हैं और वर्षों पहले बनाई गई थीं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि स्कूलों की जर्जर छात्रों के हितों के लिए आवाज उठाती रहेगी। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद

हिमालयी जलवायु संकट पर नेपाल के पीएम शाह ने दुनिया से मांगा ठोस जवाब

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि नेपाल को जलवायु परिवर्तन के कारण सामने आ रही आपदाओं की गंभीरता को दुनिया के सामने और मजबूती से रखना होगा। प्लेश फ्लड को आठ दिन बीत चुके हैं और विनाशकारी बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या 1,100 के पार पहुंच गई है। प्रतिनिधि सभा (नेपाली संसद का निचला सदन) को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं रह गए हैं, बल्कि वे मानव जीवन, बुनियादी ढांचे और भविष्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण



(एनडीआरआरएमए) के अनुसार, बुधवार सुबह 9 बजे तक पिछले सप्ताह आई बाढ़ में बह गए 1,114 शव बरामद किए जा चुके थे, जबकि करीब 3,916 लोग अब भी लापता हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के पास भोटेकोशी नदी की सहायक नदी लेंगडे खोला में हिमस्खलन के कारण पानी का प्राकृतिक अवरोध बन गया था। बाद में पानी के भारी दबाव से यह प्राकृतिक बांध टूट गया और अचानक आई

बाढ़ ने भारी मात्रा में पानी, कीचड़ और मलबे के साथ नीचे की ओर तबाही मचा दी। बाढ़ आगे त्रिशूली नदी की ओर बड़ी और रास्ते में बस्तियों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि इस आपदा ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह घटना इतनी भयावह कैसे हुई और भविष्य में नेपाल को ऐसी आपदाओं के लिए किस तरह तैयार होना होगा? उन्होंने कहा, ‘जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अचानक सामने आई इस बड़ी आपदा ने हमें चीबीसों घंटे नुकसान को नियंत्रित करने में जुटे रहने को मजबूर कर दिया है। साथ ही हमारे मन में एक गहरा सवाल भी उठा है कि आखिर यह आपदा हमारे सामने कैसे आई? ‘ शाह ने विशेषज्ञों के आकलन का हवाला

देते हुए कहा कि यह घटना हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जोखिमों की गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा, ‘हमें जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप सामने आ रही आपदाओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जागरूक करना होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है। इसके प्रभावों से निपटना और उन्हें कम करने के प्रयास पूरी वैश्विक समुदाय की साझा जिम्मेदारी है।’

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते चेतावनी पहुंचाने में सरकार को भूमिका पर उठे सवालों का भी शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा, ‘जैसे ही हमें जानकारी मिली कि बाढ़ आ रही है, हमारे सुरक्षा कर्मियों को लोगों को सतर्क करने के लिए तैनात किया गया। हालांकि, वे खुद इस अभियान के दौरान लापता हो गए।’

गांधीनगर(एजेंसी)। गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मेहसाणा जिले से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे साइबर ठगी करने वाले गिरोह को बल्क मोड सुविधा वाले कॉंपैरेंट बैंक खाते उपलब्ध करा रहे थे। जांच में पता चला है कि इन खातों का इस्तेमाल कई राज्यों में हुई साइबर ठगी के मामलों में किया गया, जिनमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। यह गिरफ्तारी ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0’ के तहत की गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पार्थ बारोट और रमेश कुमार लवाणा के रूप में हुई है। दोनों मेहसाणा जिले के विसनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को विसनगर से पकड़ा और कानूनी प्रक्रिया के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार, इस मामले में अब तक छह अन्य

आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि बारोट और लवाणा लोगों से बैंक खाते हासिल करके साइबर ठगी गिरोह तक पहुंचाते थे। गिरोह खासतौर पर उन खातों की मांग करता था, जिनमें बल्क मोड सुविधा होती है। इस सुविधा के जरिए एक साथ कई लेनदेन या भुगतान किए जा सकते हैं। यह आमतौर पर व्यावसायिक, कॉंपैरेंट, सरकारी या संस्थागत खातों में उपलब्ध होती है, न कि सामान्य बचत खातों में। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऐसे खाताधारकों को कमीशन का लालच देते थे। इसके बदले वे उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक की तस्वीरें, एटीएम कार्ड के आगे और पीछे की फोटो, इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारीयां हासिल कर

पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका का सुरक्षा अलर्ट



नागरिक संभावित उड़ान रद्द होने, हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में व्यवधान के लिए तैयार रहें। नागरिकों को अपनी उड़ानों की स्थिति संबंधित एयरलाइन से सीधे जांचने और हवाईअड्डों तथा विमानन सेवाओं से जुड़ी ताजा सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व के बाहर स्थित अमेरिकी में कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी

बच्चों के अपहरण पर सख्त कानून की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

नई दिल्ली(एजेंसी)। देश में बच्चों की बढ़ते अपहरण और मानव तस्करी के मामलों को लेकर कानून सख्त करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में बच्चों की तस्करी, अवैध गोद लेने और शोषण के लिए चल रहे कथित संगठित गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि लापता और अपहृत बच्चों के मामलों में सक्रिय था और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवजात बच्चों को कथित तौर पर लाखों रुपये में बेचता था। याचिका में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता बताई गई है।

विशेष अदालतों के गठन की मांग भी की गई है। याचिका में बिहार समेत कई राज्यों में बच्चों के लापता होने और मानव तस्करी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि नाबालिगों को बाल मजदूरी, भीख मांगने, यौन शोषण और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेला जाता है। याचिका में दिल्ली पुलिस की ओर से जून 2026 में पकड़े गए कथित बाल तस्करी गिरोह का भी उल्लेख किया गया है। दावा है कि गिरोह पांच राज्यों में सक्रिय था और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवजात बच्चों को कथित तौर पर लाखों रुपये में बेचता था। याचिका में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता बताई गई है।



इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय, बिहार के पूर्व डीजीपी डॉ. परेश सक्सेना और पूर्व आईएस अधिकारी दिनेश चंद्र के नाम शामिल थे। विचार-विमर्श के बाद ट्रस्ट ने जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने छह दिसंबर 1986 को लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया था।

कमांडिंग-इन-चीफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा एकीकृत रक्षा स्टाफ में उप प्रमुख समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उन्हें संचालन, रणनीतिक योजना, नेतृत्व और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का व्यापक अनुभव है। उनका सैन्य करियर कई संवेदनशील और रणनीतिक

जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व करने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी। ऐसे में अयोध्या में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय में उनके अनुभव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

फसलों के बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, 30 सितंबर तक किसान करा सकेंगे आवेदन

उन्नाव। रबी सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में तोरिया, सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर और गेहूँ समेत प्रमुख रबी फसलों के बीजों का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। किसानों की सुविधा के लिए बीजों की ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने बताया कि इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल222.agriculture.up.gov.in ?? पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण एवं बीज की बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी जरूरत के अनुसार बीज की बुकिंग करा लें। ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए किसान घर बैठे बीज बुक कर सकेंगे। साथ ही सरकारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध बीज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य रबी फसलों की बुवाई से पहले किसानों को समय से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें तथा बुकिंग पूरी होने के बाद संबंधित विवरण सुरक्षित रखें, ताकि बीज प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

शशक्त बृथ से भाजपा होगी मजबूत: पवन

देवरिया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के बरियारपुर मंडल के महुआपाटन स्थित खाकी बाबा मंदिर परिसर में भाजपा मंडल कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें मंडल कार्यसमिति और बृथ कार्यसमिति सत्यापन अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि से हुई। मुख्य अतिथि मंडल प्रवासी एवं भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्र ने कहा कि चुनाव जीतने का रास्ता बृथ से होकर जाता है। इसलिए बृथ स्तर के संगठन को मजबूत करना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंडल और बृथ कार्यसमितियों को सशक्त बनाने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है। कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से अभियान को पूरा करें। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व

सोन नदी के उफान से अड़गुड़ नाला बना बेहद खतरनाक, जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे पार कर रहे ग्रामीण

पोखरिया पुलिस चौकी का कोन थाने से संपर्क टूटा; बिहार आने-जाने का रास्ता भी बंद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोन /सोनभद्र- उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत बसुहारी का अड़गुड़ नाला इन दिनों सोन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बेहद खतरनाक हो गया है। नाले में करीब 10 से 15 फीट तक पानी भर जाने से क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। हालात यह है कि ग्रामीण और राहगीर जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नाला पार करने को मजबूर हैं। गहरे पानी और तेज बहाव के कारण कृषि भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। मंगलवार को अड़गुड़ नाले की गंभीर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन सोनभद्र के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकुमार जायसवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि कोन दिनेश कुमार गुप्ता, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक हृदय निवास पाण्डेय सहित तरिया क्षेत्र के शिवम कुमार प्रजापति, अजीत कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे। टीम ने नाले का

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 व 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उन्नाव। जवाहर नवोदय विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु लेटरल एंट्री मिलेक्शन टेस्ट (स्थासू-2027) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय की प्राचार्या प्रतिमा पुरी ने बताया कि कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्र का शैक्षिक सत्र 2026-27 में जनपद उन्नाव के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययन प्रशासन ने पात्र जरूरी है। छात्र उन्नाव का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी जन्म तिथि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए।

स्ट्रॉटर हाउसों ने उन्नाव की आबो-हवा में घोला ‘जहर’, जिम्मेदार बेखबर

अपशिष्ट निस्तारण से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तककठघरे में व्यवस्था

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उन्नाव। दही औद्योगिक क्षेत्र में संचालित स्ट्रॉटर हाउसों से निकलने वाले अपशिष्ट और दुर्गंध को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। रूस्म स्ट्रॉटर हाउस को लेकर स्थानीय स्तर पर खुले में पशु अपशिष्ट, गंदे पानी के निस्तारण और तेज दुर्गंध फैलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन मौजूदा आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में इसी औद्योगिक क्षेत्र के स्ट्रॉटर हाउसों से जुड़े प्रदूषण और अपशिष्ट निस्तारण को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। २०२५ में सामने आई थी खुले अपशिष्ट की समस्या अगस्त 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दही औद्योगिक क्षेत्र में संचालित सात स्ट्रॉटर हाउसों पर पशु अपशिष्टों को खुले वाहनों से बाहर ले जाने और खुले में फेंके जाने के आरोप सामने आए थे। रिपोर्ट में बताया गया



था कि पशु अवशेषों के उचित निस्तारण और परिवहन के नियमों की अनदेखी से स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में है। आसपास के गांवों की करीब 1.50 लाख आबादी पर इसका असर पड़ने की आशंका भी जताई गई थी। २०२२ में छह स्ट्रॉटर हाउसों को नोटिस इससे पहले मार्च 2022 में यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक क्षेत्र की लोनी और सिटी ड्रेन में टैंकरों के जरिए अपशिष्ट गिराए जाने की शिकायतों के बाद छह स्ट्रॉटर हाउस और 54 टेंनरियों को नोटिस जारी किया था। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ड्रेन के पानी के नमूनों की जांच में

ब्रह्म और श्रद्धा की मात्रा कई गुना अधिक पाई गई थी तथा अन्य हानिकारक रसायनों की मौजूदगी की भी बात सामने आई थी। ईटीपी और दुर्गंध नियंत्रण पर भी उठ चुके हैं सवाल दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र के एक स्ट्रॉटर हाउस की पूर्व जांच में ईटीपी की पाइपलाइन में रिसाव, दुर्गंध रोकने वाला बायोफिल्टर खराब मिलने और मांस के टुकड़े व अपशिष्ट खुले स्थान पर पड़े मिलने की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। अधिकारियों ने ईटीपी दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी।

जनपद में हो रही लगातार बारिश से गरीबों का आशियाना उजड़ने का सता रहा डर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोन / सोनभद्र – सदर विधान सभा के ओबरा तहसील के ग्राम पंचायत कुड़वा के टोला तुमियां कमरान टोला में कनहर डिवीजन 6 के द्वारा नहर किनारे सड़क का निर्माण कराया गया था जो बारिश के दिनों में मुसीबत बन गया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त बांध कई वर्ष पहले भूमि संरक्षण विभाग से वर्ष 1985 में बांध बनवाया गया था जिसमें बांध से पानी निकालने के लिए कई निकास द्वार बनाये गये थे जो सड़क बनाने के लिए कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण खंड 6 द्वारा पेशानी का सबब बना हुआ है। जिसके क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित विभाग को अवगत कराया जा चुका है फिर भी उनके कान तक आदिवासियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जिससे क्षुब्ध होकर

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 से कारीगरों को मिलेगा सहारा, 10 लाख तक बिना गारंटी व ब्याज मुक्त ऋण

उन्नाव। पारंपरिक एवं आधुनिक ट्रेड से जुड़े कारीगरों की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 लागू की गई है। योजना के तहत पात्र कारीगरों को अपना कारोबार शुरू करने अथवा उसे विस्तार देने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण, 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ बिना गारंटी और बिना ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त उद्योग मोहम्मद सउद ने बताया कि योजना के तहत जनपद में पारंपरिक और आधुनिक ट्रेड से जुड़े कुल 14 प्रकार के कारीगरों को लाभ मिलेगा। इनमें मूर्तिकार, मालाकार, धूधवाला, भरभूजा, मछुआरा, मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत सामान की मरम्मत, प्लम्बर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टालेशन, डिजिटल फोटोग्राफी तथा सौंदर्य एवं वेलनेस जैसे कार्य शामिल हैं। योजना में कारीगरों को उनके उद्यम से संबंधित 10 दिवसीय कौशल वृद्धि प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सफल प्रशिक्षार्थियों को सेवा अथवा व्यवसाय के संचालन के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कारीगरों को परियोजना लागत के अनुसार 10 लाख रुपये

शक्तिनगर पुलिस की बड़ी सफलता, 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शक्तिनगर / सोनभद्र – पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के कुशल जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर सत्येंद्र राय के नेतृत्व में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन चोरी की घटना का 36 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे एवं निशानदेही से चोरी की बोलेरो गाड़ी, एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल तथा बोलेरो वाहन की नंबर प्लेट बरामद की गई। दिनांक 31.08.2026 को वादी विकास पाण्डेय पुत्र राम निवाज पाण्डेय, हाल पता- बारब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, एनटीपीसी

शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र द्वारा थाना शक्तिनगर पर लिखित तहरीर दी गई कि कम्पनी के नाम से पंजीकृत बोलेरो वाहन संख्या छ्वा1018थे0558 को दिनांक 25.08.2026 की रात्रि करीब 10:00 बजे एनटीपीसी शक्तिनगर स्थित बीएचएल गेट से करीब 50 मीटर अंदर डीएम प्लांट के पास खड़ा किया गया था। दिनांक 26.08.2026 को प्रातः करीब 08:30 बजे वाहन उक्त स्थान पर मौजूद नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद भी वाहन का कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शक्तिनगर पर मु0अ0स0-163/2026, धारा-303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया घटना के शीघ्र अनावरण एवं चोरी गए वाहन की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर द्वारा पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए पुलिस टीम द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं सुरागरसी-पतारसी के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अभिषेकवर प्रसाद दुबे को दिनांक 01.09.2026 को समय 22:03 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही एवं कब्जे से चोरी की बोलेरो वाहन, एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल तथा बोलेरो वाहन की नंबर प्लेट बरामद की गई। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों।

रात सोचने को मजबूर हैं। प्रदर्शन में मुख्य रूप से राम बेलाश गोंड, अनिल गूढ़,सुनिता,कलावती, कमला देवी, लखन,जागशाह ,जगू, रामप्यारे, हीरा लाल,लक्षुमन, दिनेश, वंशीभर,जगन्नायन शामिल रहे। इस बावत् अधिशासी अभियंता(एकशियन) कनहर डिवीजन निर्माण खंड -6 ने कहा कि जल्द ही समस्या का निराकरण करा दिया जायेगा। किसानों व रहवासियों की समस्या को देखते हुए संबंधित विभाग ने मौके पर जे सी बी भेजा जिससे देखकर किसान रामचंद्र, रामधनी, कैलास, विनोद, नंदू, मुन्ना, क्रमोद आदि विरोध करने लगे। विरोध के कारण मामला जस का तश रहा। किसानों का आरोप है कि अगर बांध काट दिया जाये तो बांध के नीचे के किसानों के दर्जनों किसानों की धान की फसल चोपट हो जायेगी इसके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य मशीनों की सहायता से बांध का पानी मुआवजा दिलाया जाय।

रात सोचने को मजबूर हैं। प्रदर्शन में मुख्य रूप से राम बेलाश गोंड, अनिल गूढ़,सुनिता,कलावती, कमला देवी, लखन,जागशाह ,जगू, रामप्यारे, हीरा लाल,लक्षुमन, दिनेश, वंशीभर,जगन्नायन शामिल रहे। इस बावत् अधिशासी अभियंता(एकशियन) कनहर डिवीजन निर्माण खंड -6 ने कहा कि जल्द ही समस्या का निराकरण करा दिया जायेगा। किसानों व रहवासियों की समस्या को देखते हुए संबंधित विभाग ने मौके पर जे सी बी भेजा जिससे देखकर किसान रामचंद्र, रामधनी, कैलास, विनोद, नंदू, मुन्ना, क्रमोद आदि विरोध करने लगे। विरोध के कारण मामला जस का तश रहा। किसानों का आरोप है कि अगर बांध काट दिया जाये तो बांध के नीचे के किसानों के दर्जनों किसानों की धान की फसल चोपट हो जायेगी इसके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य मशीनों की सहायता से बांध का पानी मुआवजा दिलाया जाय।

आउटसोर्स कर्मिकों को मिलेगा सम्मान, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश – श्रम का सम्मान, सेवा की सुरक्षा और श्रमिक परिवारों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के क्रम में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के संबोधन का विकास भवन स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में सजीव प्रसारण देखा एवं सुना गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक एवं आउटसोर्स कर्मिक शामिल हुए मुख्यमंत्री के सम्बोधन के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मिकों निगम के गठन वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुविधा और हित किये गये निर्णय की मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा का उपस्थित कर्मिकों ने तालियों की गड़गड़हाट से स्वागत किये और प्रसन्नता व्यक्त किये इस अवसर पर विधायक सदर भूपेश चौबे , जिलाधिकारी चर्चित गौड़, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, ब्लाक प्रमुख सदर अजीत रावत, राज्यमंत्री के प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी, अपर

एडवर्स एन्ट्री की कार्यवाही की जाये। उन्होंने बैठक के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये तथा जो कर्मी साफ-सफाई के लिये नियुक्त किया गया है उसके कार्यों में लापरवाही पायी जाती है तो चयनित एजेंसी को सूचित कर तत्काल हटायें जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाये।

डी0पी0ओ0 आई0सी0डी0एस0 को निर्देशित किया गया कि आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा नियमित रूप से आशा आगनबाड़ी जाये इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के प्रगति की समीक्षा की जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुद्धी की प्रगति धीमी पायी गयी जिसके लिए उन्होंने सम्बन्धित सी0एच0ओ0 और डी0पी0एम0 के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिये और प्रगति में अपेक्षित सुधार न होने पर अगले माह में एम0वाई0सी0 के विरुद्ध

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सीएचसी की सभी मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश-मुख्य विकास अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश – जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने जनपद के समस्त चिकित्सा अधीक्षकों (एमओआईसी) को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपदवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता एवं आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0 विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि एन0आर0सी0 सेक्टर में सैम मैम बच्चों को भर्ती करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये जिससे की अति दुर्बल बच्चें जल्द स्वस्थ हो सके इस दौरान



उन्होंने कहा कि जिन आशाओं द्वारा डिलवरी अस्पतालों में एक भी नहीं करायी गयी है उन्हें नोटिस देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के प्रगति की समीक्षा की जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुद्धी की प्रगति धीमी पायी गयी जिसके लिए उन्होंने सम्बन्धित सी0एच0ओ0 और डी0पी0एम0 के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिये और प्रगति में अपेक्षित सुधार न होने पर अगले माह में एम0वाई0सी0 के विरुद्ध

आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, उन्नाव के 1449 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

निराला प्रेक्षागृह सभागार में सोमवार को उर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के लोगो के अनावरण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उन्नाव। निराला प्रेक्षागृह सभागार में सोमवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के लोगो के अनावरण, वेबसाइट एवं पोर्टल के शुभारंभ तथा आउटसोर्स कर्मियों के बढ़े हुए पारिश्रमिक की घोषणा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शशील कुमार गोंड तथा सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा उपायोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सभागार में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों ने देखा। कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो एवं



वेबसाइट का शुभारंभ किया गया तथा बढ़े हुए पारिश्रमिक की घोषणा के साथ प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर कर्मियों को सम्मानित किया गया। नई व्यवस्था के तहत कुशल श्रमिकों, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के लिए 22 हजार रुपये तक तथा अकुशल श्रमिकों के लिए 20 हजार रुपये तक पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है। साथ ही आउटसोर्स एजेंसियों को प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख के बीच कर्मियों का पारिश्रमिक

उपलब्ध कराने तथा ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

व्यवस्था के तहत कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा एससी/एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिलाओं, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात कही गई। उन्नाव जिले की 19 नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में कार्यरत 1449 आउटसोर्स कर्मियों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद उन्नाव के सफाई कर्मियों और सौवर सफाई आउटसोर्स कर्मियों को सेवा कार्य में

उपयोगी किट भी वितरित की गई। श्रम विभाग की ओर से कन्या विवाह सहायता योजना के छह लाभार्थियों को 65-65 हजार रुपये के प्रतीकात्मक चेक तथा मातुत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के 13 लाभार्थियों को चेक प्रदान किए गए। इस दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता ने सरकार के निर्णय का आउटसोर्स कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक तेजवंत बात कही गई। उन्नाव जिले की 19 नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में कार्यरत 1449 आउटसोर्स कर्मियों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद उन्नाव के सफाई कर्मियों और सौवर सफाई आउटसोर्स कर्मियों को सेवा कार्य में



नगर कार्यकारिणी की शपथ दिलाई इस
असपर प कुंवर हरि सिंह बुंदेला संरक्षक
डॉक्टर जितेंद्र जैन तहसील अध्यक्ष
उपाध्यक्ष विशाल यादव, नीज
बडैरिया, अभिनव गुप्ता, कुलदीप छी
कुलदीप गुप्ता, अरवि जैन, सुचनेंद्र
अजय जैन तहसील महामंत्री विवेक
गुप्ता शरद सोनी तालबेद, तहसील
मंत्री जयपाल राजा जखौरा, सोनु
कोरौसिया, गुड्डे राजा बार, दीपक पाटकर
रूपेश गुप्ता भार, रामपाल झा, तातबेद
राहु राघवेंद्र यादव मीडिया प्रभारी, अमिल
शर्मा, नगर इकाई संरक्षक ओम सेठ,
रत्नमणी गुप्ता, बट्टी मोदी, महेश सेठ उमेश
शर्मा अध्यक्ष, सावन सोनी संगठन
मंत्री, कोषाध्यक्ष दीपक बज्जरी, उपाध्यक्ष
मनोज जैन, सचेंद्र नामदेव, अरुण
गंगोले, महेंद्र सोनी, धनीराम कोरी, विजिप
सोनी, महामंत्री प्रिंस बुंदेला अनुज
सासाह, सीरधर साहू मंद प यादवेंद्र
यादव, गोविंद पाटकर, जितेंद्र
गुप्ता, अशोक गोस्वामी आनंद
कुशावाह, रामकिशोर कुशाबाह, दिनेश
अमित सुनार, आनंद कुशाबाह, भरत
साहू, कृष्णगोपाल सोनी, मीडिया प्रभारी
अभिषेक गुप्ता, संदीप झा कार्यकारिणी
अभिषेक सेठ , रवि गुप्ता, सीरधर
गुप्ता, गौरव गुप्ता, मलखन सिंह, गबर

